

## प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली दिनांक 9 जुलाई 2010

### दीर्घकालीन अवसंरचना बांड

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों को विनिर्दिष्ट किया है; (i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम; (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम; (iii) अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लिमिटेड; तथा (iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी; आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए "दीर्घकालिक अवसंरचना बांड" के रूप में। इन बांड में बीस हजार रुपये तक का निवेश करदाता की कुल आय से कटौती के लिए पात्र होगा। यह कटौती अधिनियम की धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत अनुमत एक लाख रुपये की कटौती के अतिरिक्त होगी।

बॉन्ड का कार्यकाल न्यूनतम दस वर्ष होगा, जिसमें निवेशक के लिए पाँच वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी। बॉन्ड में निवेश हेतु ग्राहक द्वारा जारीकर्ता को स्थायी खाता संख्या प्रदान करना अनिवार्य होगा।

[अधिसूचना संख्या 48/2010 दिनांक 9 जुलाई 2010; एफ.सं.149/84/2010-एसओ (टीपीएल)]

XXX